

"युद्धो अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 17 फरवरी 2025 सोमवार

सम्पादकीय

विवादों में निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग लगातार विवादों में है। पिछले कुछ वर्षों में उसकी निष्पक्षता पर अनेक बार सवाल उठे हैं। जिस प्रकार के आरोप उस पर लगते रहे हैं, वह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार ईवीएम से जुड़ी शिकायतें आज तक दूर नहीं कर सका है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगली अठारह फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अतः नई नियुक्ति केंद्र की ओर से वर्ष 2023 में लाए गए नए कानून के तहत हो सकती है। इस पर भी सवाल उठे हैं। इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय का कड़ा रुख दिख रहा है। उसने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बीच कुछ भी घटित होता है, तो उसके परिणाम अवश्य भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की स्वतंत्र समिति कर, पर सरकार ने समिति से प्रधान न्यायाधीश को हटा दिया और उनकी जगह किसी मंत्री को सदस्य बना दिया। यह चुनावी लोकतंत्र के विरुद्ध माना गया। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र की इच्छा पर निर्भर हो गई है। विरोध इसी बात का है।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से नागरिकों का जिस तरह भरोसा कमजोर हुआ है, वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। दाम्नी नेता आज भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आयोग उन्हें रोक नहीं पा रहा। वहीं आरोप संहिता के उल्लंघन पर कर कार्रवाई में उसकी निष्पक्षता संदिग्ध दिखती है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के भी गंभीर आरोप हैं। वह चाहे जितनी दलीलें दे, लेकिन हकीकत है कि कई राजनीतिक दल और मतदाता ईवीएम से संतुष्ट नहीं हैं।

आयोग ईवीएम में संग्रहीत आंकड़े बताते तक से इनकार करता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि ईवीएम में संग्रहीत आंकड़ों को न हटाया जाए। दरअसल, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने याचिका दायर की है कि जल जूई ईवीएम की 'मेमोरी' और 'माइक्रोकंट्रोलर' को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है। मगर याह सवाल सत्यापन से अधिक संदेह का है। आरोपों से धिरे आरोपों को जवाब देना ही होगा।

गुम होते ग्लेशियर

अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक, ग्लेशियर चूंकि प्राकृतिक मीठे पानी के भंडार के रूप में काम करते हैं और पृथ्वी की जलवायु तथा जल चक्र को विनियमित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, ऐसे में, ग्लेशियरों के पिघलने से मीठे पानी की उपलब्धता, वितरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी असर पड़ता है। एक नया अध्ययन बताता है कि अंटार्कटिक प्रदेश में, पूर्वी हिमालय के एक हिस्से में पिछले 32 साल यानी करीब तीन दशक में 110 ग्लेशियर नष्ट हो गए। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा अध्ययन में यह पाया गया कि ये ग्लेशियर 1988 से 2020 की अवधि में सालाना 16.94 वर्ग किलोमीटर की वापसी की दर से गायब हो रहे थे, यही नहीं, ग्लेशियरों के झील बनने और इनके फटने से अब बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।

अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक, ग्लेशियर चूंकि प्राकृतिक मीठे पानी के भंडार के रूप में काम करते हैं और पृथ्वी की जलवायु तथा जल चक्र को विनियमित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, ऐसे में, ग्लेशियरों के पिघलने से मीठे पानी की उपलब्धता, वितरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी असर पड़ता है, इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसा कि 2023 में सिकिम में आयी आपदा के रूप में देखा गया था, जिसमें कम-से-कम 55 लोग मारे गये थे और 1,200 मेगावाट की एक जलविद्युत परियोजना नष्ट हो गयी थी।

ग्लोबल विश्वविश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा किया गया यह अध्ययन जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में छापे जा चुका है। शोधकर्ताओं ने ग्लेशियर की सीमाओं का मानचित्रण करने के लिए एलांग से लेकर लाइबत अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली का इस्तेमाल किया। ग्लेशियरों का पीछे हटना, जाहिर है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख संकेतक है, यह वह प्रक्रिया है, जिसमें ग्लेशियर नयी बर्फ और बर्फ के जमा होने की तुलना में तेजी से पिघलते हैं।

अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि 32 साल की अवधि के दौरान ग्लेशियरों की संख्या 756 से घट कर 646 रह गयी। ग्लेशियर कवर 585.23 वर्ग किलोमीटर से घट कर 309.85 वर्ग किलोमीटर रह गया, जो 47 फीसदी से अधिक का नुकसान है। अध्ययन में एक चिंता की बात यह है कि हिमालय के ग्लेशियर वैश्विक स्तर पर अन्य ग्लेशियरों की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं, उसमें भी पूर्वी हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने की दर वैश्विक औसत से अधिक है। ग्लेशियर क्षेत्रीय जल संचयन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लाखों लोगों को जीवित रखने वाली नदियों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। ऐसे में, बेहतर निगरानी प्रणाली, टिकाऊ जल प्रबंधन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की नीति अपनायी जाये, ताकि बचे ग्लेशियरों को बनाया जा सके।

अभिनय आकाश—

लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, पुना हुआ बरित्र देश का इसे कहीं से लओगे।

हम सभी का बचपन ऐसी कहानियों को पढ़कर, सुनकर बीता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सेनानायक दुश्मन की एक महिला को लूट लाया और कहा कि आपके लिए मैं इस खूबसूरत लड़की को लेकर आया हूं। तो शिवाजी ने उस सेनानायक को डांट और उस लड़की से कहा कि मैं अपने सेनापति की ओर से क्षमा चाहता हूं। आप बड़ी खूबसूरत हैं, मेरी मैं भी आप जैसी सुंदर होंगी तो मैं भी आप जैसा सुंदर होता। ऐसा कहने वाला शिवाजी हमें पढ़ाया गया। आपसे एक सवाल करूं कि भगवान से कौन बड़ा है? भगवान से मां बड़ी है, जिससे भगवान पैदा किया है। इसलिए तुलसीदास जी भी शुरुआत में ही प्रणाम करते हुए कहते हैं बंदर कोशल्या दिसि प्राची। प्राची दिशा के समान कोशल्या हैं उन्हें प्रणाम करता हूं, जिनकी कोश्या से सूर्यवर्षी राम पैदा हुए। प्रभुगुप्त को जब 14 सालों का बनवास हुआ तो जब वो अपनी मां के पास गए तो कोशल्या ने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मां मुझे जंगल भेज दिया गया। भयानक तो राजा बना दिया। रिक्षित्सर छिन लिया गया। राम ने कहा कि पिता देहिं मोहि कानन राजू यानी पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया। हा जंगल का राजा बन गया। जह संज मौंति मोर बड़ काजू यानी जहां मेरे सारे बड़े काम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब अपने 14 बरस के बनवास को भी इतनी सहसा से प्रस्तुत करने वाले राम ही हो सकते हैं। ये बनाते हैं मकसद है कि हमारी जड़ें कहाँ से



जुड़ी हैं। भारत एक पारिवारिक और संस्कारों का देश है। इस समय भारत में सबसे पवित्र महाकुंभ का समय चल रहा है। देश के करोड़ों परिवार अपने माता पिता और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। भारात श्रवण कुमार का देश है और याह माता पिता को पूजनीय माना जाता है। लेकिन जिस समय देश के करोड़ों परिवार महाकुंभ की आस्था में डूबे हुए हैं। देश के कुछ यूट्यूबर माता पिता को लेकर बहुत ही अदभ्य और अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं। इसने बड़ी आसानी से वो शब्द कहा है जो लेकिन हम उन शब्दों को आपके सामने रख नहीं सकते। हम आपके परिवार की आस्था और संस्कारों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम इस शब्द के दौरान न ही हमें मटुबुकर को नाम लेगे और क्योंकि हम इसे वायरल नहीं करना चाहते। हम इसे वो नहीं देना चाहते जो ये चाहता है। हम इसके यूट्यूब नहीं बढाना चाहते जो ऐसे लोग चाहते हैं। न ही हमें इसे कोई विलेन बनाने की मंशा है। वस

हम ये बातना चाहते हैं कि ऐसे लोग भारत के संस्कारों का अपमान करने हैं। फिर कानूनी एक्शन होने पर माफी मांगते हैं, थोड़ा आसूं बहा लेते। जो कुछ महीने या दिन की जेल काट अपने मेन गैल को प्राप्त कर जाते हैं। आजकल आपने एक शब्द सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स खूब सुना होगा। या फिर यूट्यूबर्स या रील्स बनाने वाले। पिछले कुछ वर्षों में यूट्यूबर्स की एक नई बीड आ गई है। जो पोंडकारट बनती है। बीडियो बनाती हैं। जो उस चले रहती है। लोग जानते हैं कि इनके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। इसलिए ये सबसे आसान रास्ता अपनकर मद्ध और अश्लील कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का रास्ता चुनते हैं। जिन यूट्यूबर्स ने गंदी बातें की, अपनी मां के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वो माफ़ी के लायक तो नहीं हैं क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई। जो कुछ कहा गया वो सोच समझकर, लिखी गई रिफ्ट के आधार पर कहा गया। ये

अश्लील बीडियो आप बनाएंगे। जितने ज्यादा नए नए विवाद आप पैदा करेंगे। उतने ज्यादा यूज आपको मिलेंगे। अतः ज्यादा आप वायरल होंगे। एक अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है। जिसमें हर यूट्यूबर ज्यादा से ज्यादा यूज चाहता है। पैसा कमाना चाहता है। लेकिन सबसे हेरान करने वाली बात है कि देश का एक बड़ा वर्ग उन्हें न केवल देख रहा है बल्कि उस पर तालियां बजा रहा है। आज भारत जैसे संस्कारी देश में तमाम इंफ्लूएंसर्स के बीच यूज पाने की रेस चल रही है। लोग जानते हैं कि इनके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। इसलिए ये सबसे आसान रास्ता अपनकर मद्ध और अश्लील कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का रास्ता चुनते हैं। जिन यूट्यूबर्स ने गंदी बातें की, अपनी मां के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वो माफ़ी के लायक तो नहीं हैं क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई। जो कुछ कहा गया वो सोच समझकर, लिखी गई रिफ्ट के आधार पर कहा गया। ये

कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ये अपनी मजाकिया टिप्पणियों की वजह से काफी चर्चा में रहा था। इतना की विवादित लोगों को स्वयं के साथ गले लगाने वाला टीवी शो उन्हें न केवल बुलाता है। बल्कि वो तो विनम्र बनकर ही बाहर निकलता है। इससे पहले भी वो ओटीटी एप पर आने वाले एक शो को अंटी टी चुका होता है। मतलब सीसी साफ फुल है कुछ भी गंद बोला, धर्म के रूप टिप्पणी करो, बस केवल सिर तन से जुदा वाले को छोड़कर तो एक खास वर्ग आपको कुल समझने लगेंगे। आप प्रतिदि पाने लगेंगे।

चरित्र का वायरस जो नुकसान करवा वो कोरेना भी नहीं कर सकता। क्योंकि कोरेना तो शरीर को ही मारता था, ये तो आत्मा को मार देता है। ये देश सरकारों, नेताओं, पार्टियों से नहीं बना। ये देश मेरे और आपके जैसे लोगों ने बनाया है। एकात्म पराक्रम यानी हमने अकेले में पराक्रम किया, मतलब कोई मछली के प्रोटेक्टर का लड़का लड़कान बन गया, कोई ओमान के पेट्रोलपंप पर पेट्रोल भरने वाला आया और बीरुमाई अंजनी बन गया। कोई उड़नगर के रेलवे स्टेशन पर अपने बाप की चाय की एक पकड़ाने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये सब सरकारों की योजनाओं के काम नहीं थे। अकेले एक आदमी ने मेहनत की। एक के बाद एक होते हुए लोग की घटनाओं के बाद साफल हमारे और आपके लिए भी है कि इस तरह के लोगों को इंफ्लूएंसर्स कहते हैं उन्हें समझना होगा कि फोलाइड, ऐसे लोगों का इन्फ्लूएंस अस्थायी होता है। विश्वसनीयता के लिए, लोगों के दिलों में लंबे समय तक जगह बनाने के लिए नैतिक बात और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।

ट्रेन अग्निकांड के पीड़ितों के बारे में अपनी मजाकिया टिप्पणियों की वजह से काफी चर्चा में रहा था। इतना की विवादित लोगों को स्वयं के साथ गले लगाने वाला टीवी शो उन्हें न केवल बुलाता है। बल्कि वो तो विनम्र बनकर ही बाहर निकलता है। इससे पहले भी वो ओटीटी एप पर आने वाले एक शो को अंटी टी चुका होता है। मतलब सीसी साफ फुल है कुछ भी गंद बोला, धर्म के रूप टिप्पणी करो, बस केवल सिर तन से जुदा वाले को छोड़कर तो एक खास वर्ग आपको कुल समझने लगेंगे। आप प्रतिदि पाने लगेंगे।

खिलौनों की दुनिया में रोजगार के अवसर

—नेरेंद्र कुमार—

भारत का मौजूदा खिलौना उद्योग लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसकी वैश्विक बाजार में वृद्धिकर 0.75 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं इस उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। साल 2016-17 में इस उद्योग में लगभग 15 हजार उद्यमी थे और करीब 37 हजार लोगों को इसमें काम मिला हुआ था। हाल के वर्षों में देश में देसी खिलौना उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और साल 2025-26 के आम बजट में इसकी प्रोत्साहनी की गयी है, राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना' की शुरुआत से। जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस योजना के तहत कस्तरत विकास, कौशल उन्नयन और निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर जोर दिया जायेगा, जिससे देश में उच्च गुणवत्ता वाले और मासिक खिलौनों को प्रोत्साहित करने वाले खिलौना का उत्पादन संभव हो सकेगा। खिलौनों के वैश्विक बाजार में 'मेड इन इंडिया' ब्रांड को मजबूती देने की कोशिश की जायेगी। इस उद्योग में बहुत तेजी से विकास की संभावना है। इसलिए जल्द ही खिलौना उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा।

दरअसल राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना खिलौना उद्योग को महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। खिलौना निर्माण के लिए विशेष कस्तरत बनाये जाएंगे जिनमें छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। खिलौना निर्माण की इकाइयों के लिए बुनियादी संरचना उपलब्ध करने का आश्वासन दिया जायेगा। ये इकाइयों को टेक्स से दूर रखी जायेगी और हर तरह सहजता दी जायेगी। वहीं कौशल और श्रमिकों को नयी तकनीकों और डिजाइनों की ट्रेनिंग दी जायेगी। सरकार स्थानीय डिजाइनों और उसमें भारतीय संस्कृति के समावेश को बढ़ावा देगी और भारतीय खिलौनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन योजना भी लागू करेगी। विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने की भी बात करी है। स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भारतीय खिलौना उद्योग खूब फले फूलेंगा। भरपूर निवेश आयेगा। नये स्टार्टअप शुरू होंगे। जाहिर है, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, जो करियर के लिहाज से खिलौना उद्योग को



महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्मित करेगा।

इस क्षेत्र में विशेषकर डिजाइन और डिवाइसिंग के फ़िल्ड में कई तरह के कुशल खिलौना डिजाइनरों की मांग है। प्रमुख रूप से टॉय डिजाइनर जो खिलौनों के नये नये डिजाइन तैयार करते हैं, प्रोडक्ट्स डेवेलप जो इस उद्योग कंसेप्ट से प्रोटोटाइप तक का काम करता है और ग्राफ़िक्स/आर्ट डिजाइनर जो डिजिटल स्पॉट खिलौनों को बच्चों के अनुकूल बनाता है—एसे कुशल तकनीकीयों की मांग है। इसके अलावा खिलौना उद्योग की मैनुफ़ैक्चरिंग इकाइयों में प्रोडक्शन इंजीनियर तथा व्हालरिटी कंट्रोल एक्सपर्ट की भी जरूरत है। बिजनेस और मार्केटिंग के क्षेत्र में यहां ब्रांड मैनेजर, सेलस मैनेजर और एक्सपर्ट मैनेजर की जरूरत होती है, जो खिलौना ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, आईडिजीनर डिजाइनर, बीडियो कंटेन्ट, ब्रान्डिंग प्रमुख डिजाइनर हैं। खिलौना उद्योग में अलग-अलग प्रोफ़ेशनल्स के लिए 6 से 12 लाख रुपये तक की प्रारंभिक नौकरियां मिल सकती हैं और एक और दो साल के अनुभव के बाद 12 से 40 लाख रुपये सालाना की नौसारी बन सकती हैं। अगर इस क्षेत्र में मौजूद बड़ी बड़ी कंपनियों की बात है तो फन स्कूल इंडिया लिमिटेड, सन लॉड टॉयज, मिना टॉयज, टॉय पार्क इंडिया और रिकल मैट्रिक्स जैसी भारतीय कंपनियां तो हरिओ इंडिया, मेलो टॉयज और हास्रो इंडिया नामक बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, जो खिलौना उद्योग के प्रशिष्ठि एजीक्यूटिवों को शानदार करियर और ऑफर देते हैं। मेक इन इंडिया को वाकफ़ परफ़ेक्ट आहवानों के चलते फ़ैलू खिलौना उद्योग ताकतवर बन से उभरने के लिए तैयार है। अगर आपको क्रिएटिविटी के खिलौना उद्योग में हासिल करने का विचार बहुत सारे अवसर मौजूद हैं—इस रीसें.

डिजाइन कोर्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क बर्गिंग और इंजीनियरिंग के लिए बीटकडिल्लोमा इन लास्टिक इंजीनियरिंग करना भी इस क्षेत्र में रोजगार के लिए उपयोगी है। भारत के कई बड़े शहरों में विभिन्न तरह के स्थाना उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र के लिए एम्पलए इन मार्केटिंग/डिजिटल बिजनेस करनी हो तो सभी आईआईएमएस, एम्पलए वकीलों के एक पैरल को देकर व्यक्ति स्वतंत्रता को मजबूत किया। अंततः आंदोलन ने जनरल म्यूरफ़ के सैन्य शासन के पतन को उलटित किया, जिससे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मार्ग प्रारंभ हुआ। इन परिवर्तनों के एक ऐसी न्यायपालिका का वादा किया जो कार्यकारी शक्ति पर एक वास्तविक रूप के रूप में काम कर सकती थी। एक न्यायपालिका के पास सैन्य, नितिक अधिकारों को लागू करने, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और राज्य और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नेता को जवाबदेह ठहराने की शक्ति होनी चाहिए।

राजनीतिक दबावों के बावजूद, पाकिस्तान की न्यायपालिका ने दिखाया कि वह हासिए पर पड़े लोगों के लिए एक सुशासन के रूप में खड़ी हो सकती है। फिर भी, पाकिस्तान की न्यायपालिका के प्रति प्रस्तावना एक अविश्वसनीय क्षति बताता है, जो निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता से प्रभावित है और मुख्य, स्वतंत्र फैसलों से आकार लेती है। कम से कम 1990 के दशक से, पाकिस्तान की न्यायपालिका ने निरंतर दबाव का सामना करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन बुनियादों के बावजूद, इसने अक्सर पीछे हटते हुए, न्यायिक नियुक्तियों पर प्रभाव बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रक्राओं की पुनर्वास्था की है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने वाले ऐतिहासिक फैसले जारी किए हैं। दर्शन मसीह बनना राज्य का मामला न्यायपालिका की विकसित है—इस रीसें.

पाकिस्तान: न्यायपालिका के सामने अस्तित्व का संघर्ष

—सुल्तान महमूद—

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर चल रहा संघर्ष, जितने अधिक न्यायाधीश नित्किय दर्शन बने हुए हैं, पाकिस्तान में वकीलों के आंदोलन की याद दिलाता है। यह एक निर्णायक क्षण था जब एक मुख्य न्यायाधीश ने अपनी कर्तव्यों के बावजूद पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली लोगों से मिडने का साहस दिखाया। वकीलों और नागरिक समाज के एक बड़े पैमाने पर लाभवी ने दर्शाया कि देश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में रोजगार के उलटित किया। न्यायपालिका में जनरल म्यूरफ़ के सत्तावादी हस्तक्षेप का सामना करने, आंदोलन ने न केवल न्यायपालिका की बहाली को बढ़ावा दिया, बल्कि 18वें और 19वें संवर्धन को संवैधानिक सूरत के पक्ष को सुभान बनाया, सरकार से नियुक्तियां छीनकर उन्हें न्यायाधीशों और वकीलों के एक पैरल को देकर व्यक्ति स्वतंत्रता को मजबूत किया। अंततः आंदोलन ने जनरल म्यूरफ़ के सैन्य शासन के पतन को उलटित किया, जिससे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मार्ग प्रारंभ हुआ। इन परिवर्तनों के एक ऐसी न्यायपालिका का वादा किया जो कार्यकारी शक्ति पर एक वास्तविक रूप के रूप में काम कर सकती थी। एक न्यायपालिका के पास सैन्य, नितिक अधिकारों को लागू करने, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और राज्य और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नेता को जवाबदेह ठहराने की शक्ति होनी चाहिए।

राजनीतिक दबावों के बावजूद, पाकिस्तान की न्यायपालिका ने दिखाया कि वह हासिए पर पड़े लोगों के लिए एक सुशासन के रूप में खड़ी हो सकती है। फिर भी, पाकिस्तान की न्यायपालिका के प्रति प्रस्तावना एक अविश्वसनीय क्षति बताता है, जो निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता से प्रभावित है और मुख्य, स्वतंत्र फैसलों से आकार लेती है। कम से कम 1990 के दशक से, पाकिस्तान की न्यायपालिका ने निरंतर दबाव का सामना करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन बुनियादों के बावजूद, इसने अक्सर पीछे हटते हुए, न्यायिक नियुक्तियों पर प्रभाव बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रक्राओं की पुनर्वास्था की है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने वाले ऐतिहासिक फैसले जारी किए हैं। दर्शन मसीह बनना राज्य का मामला न्यायपालिका की विकसित है—इस रीसें.



होती भूमिका का उदाहरण है। एक सामान्य जीमीदार की हिरासत में बंधा मजदूर के एक हाताई टेलीग्राम और उसके साथ पुलिस की मिलीभगत के सत्तावादी हस्तक्षेप का सामना करने के लिए 'न्यायिक संघम' की स्थापित एंग्लो-सैलसन परंपराओं को चुनौती दी और उनकी हिलद बुनने के लिए अनुमति कराई गई। इस साहसिक कदम ने न केवल मौलिक अधिकारों की पुष्टि की, बल्कि न्यायपालिका की स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती दी और सबसे हासिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के इच्छा का भी संकेत दिया। राजनीतिक दबावों के बावजूद, पाकिस्तान की न्यायपालिका ने दिखाया कि वह हासिए पर पड़े लोगों के लिए एक मजबूत दीवार बन सकती है।

पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से लेकर सैन्य अस्त्रालात और नागरिक मुद्दमनों को संवैधानिक क्षति करने तक, ऐतिहासिक फैसलों ने कानूनी परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है। अतीत की अवज्ञा की गूज आज भी की जाती है लड़ाई को आधार देती है। 6 न्यायधीशों का पत्र इस परंपरा को एक शानदार याद दिलाता है। 2007 के बाद की अवज्ञा की भावना इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के 6 न्यायाधीशों द्वारा जून 2024 के पत्र में फिर से उभरी, जिसमें सर्वोच्च न्यायिक परिषद को संबोधित किया गया था। एक दुर्लभ सार्वजनिक टकराव में इन याचिकाओं ने न्यायिक मामलों में पाकिस्तान की अनियंत्रित सुविधा (जोसियों) के कश्ति हस्तक्षेप को उजागर किया।

दबाव, निगरानी और अपने परिवारों को धमकियों के उनके दावों ने न्यायिक स्वतंत्रता की रीति बढ़नी दिखाई। न्यायिक नियुक्तियों को रखाविक किया। वकीलों के आंदोलन के लिए न्यायपालिका के अक्षय के सबसे साहसिक कार्य के रूप में वहीत पत्र ने इस बात पर प्रकाश डाला कि

न्यायपालिका को अपनी स्वयंसेवा को बनाए रखने के लिए अभी भी किस तरह संचार करना चाहिए। पाकिस्तान की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कभी सार्वजनिक विरोध 1 और संवैधानिक सुधार की कड़ी मेहनत से हासिल की गई जित थी, अब बचे हैं। नवंबर 2024 में पारित 26वां संविधान संशोधन, अस्पष्ट परिभाषित शक्तों और अस्पष्ट अधिकारों के बीच पारित हुआ जो न्यायपालिका की संचयन को मौलिक रूप से बदल देता है। न्यायिक नियुक्तियां करने वाले न्यायाधीशों की हिस्सेदारी को कम करके, राजनीतिक नियुक्तियों को बढ़ाकर और बीच में संवचना और न्यायाधीशों के वचन में सीधे मंत्री की भागीदारी को सक्षम करके संक्षेप प्रभावी रूप से आंदोलन से नियंत्रण सरकार को स्थानांतरित करता है। यह संरचनात्मक बदलाव न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की क्षमता को कमजोर करता है, बल्कि राज्य के अतिमानव पर रोक लगाने की इसकी भूमिका को भी कमजोर करता है। सुधार की आड़ में, 18वें और 19वें संवर्धनों द्वारा स्थापित नाजुक संतुलन को उलट दिया गया है।

लोकतांत्रिक पतन हमेशा टैकों की साजिश या बंदूकों की गड़गड़ाहट के साथ नहीं आता। पाकिस्तान में, यह बंद सरकारों के पीछे हो रहा है, जिसकी पाठ में संतुष्टि बनाया है और जनता को आवश्यक सुधार के रूप में बेवा जा रहा है। वहीं न्यायपालिका को कभी तानाशाही आवेष्टान करती थी अब वास्तविक रूप से कमजोर की जा रही है, और इसकी स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है। यदि पाकिस्तान की न्यायपालिका पूर्ण राजनीतिक निरंत्रण के आगे झुक जाती है, तो राष्ट्र न केवल कानून के शासन को खो देगा, बल्कि अपने पिछले सुधारों के बदलावों पर निर्मित लोकतांत्रिक प्रगति को भी खो देगा।

